भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 375
मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए नियत

"पीएलआई योजना"

375. श्री संजय काका पाटील:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में 18,100 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ एसीसी के 50 गीगावाट घंटा (जीडब्ल्यूएच) और 'नीश' एसीसी के 5 गीगावाट घंटा (जीडब्ल्यूएच) विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 'नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमेस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज' के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के परिणामत: भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी राशि की निवल बचत हुई और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ख) : जी, हाँ। सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी है। स्कीम का कुल परिव्यय 5 वर्षों के लिए 18,000 करोड़ रूपए है। इस स्कीम में देश में एक प्रतिस्पर्धी एसीसी विनिर्माण (50 गीगावाट घंटा) व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, आला एसीसी प्रौद्योगिकियों के 5 गीगावाट घंटे को भी स्कीम में शामिल किया गया है। इस स्कीम में, प्रति किलोवाट घंटा अनुप्रयोज्य सब्सिडी और उत्पादन इकाई स्थापित करने वाले विनिर्माताओं द्वारा की गई वास्तविक बिक्री से प्राप्त मूल्य संवर्धन के प्रतिशत के आधार पर उत्पादन-संबद्ध सब्सिडी का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) : अनुमान है कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर कुल आयात बिल को लगभग 1,50,000 करोड़ रूपए तक कम किया जा सकता है। साथ ही, एसीसी कार्यक्रम से देश में वायु गुणवत्ता में सुधार आने की भी संभावना है।

*****